(b) what steps have been taken to improve the situation; and

(c) what is the content of central assistance or subsidy for the provision of smokeless chullahas and solar cookers?

THE MINISTER OF ENERGY AND THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI VASANT SATHE): (a) The use of traditional fuel in a traditional Chulha emits lot of smoke in the Kitchen which causes health hazards—such as diseases connected with respiration, heart, eyes, etc. particularly among women.

(b) Some of the steps taken by the Department of Non-Conventional Energy Sources include the following:

(1) Development and installation of fixed and portable improved chulhas which cut-out black smoke from the kitchen.

(2) Development and installation of family size community and institutional biozas plants, to supply clean cooking fuel as well as fertilizer.

(3) Popularisation and sale of family size and community size solar cookers etc.

(c) Smokeless Chulhas.

The unit cost of fixed type of chulha is Rs. 40/- to Rs. 50/-. The beneficiary has to contribute Rs. 10/- and the balance is paid by way of subsidy, by the Department.

For portable chulha the average unit cost varies from Rs. 78/- to Rs. 120|- 75 per cent subsidy is provided to the Scheduled Castes|Scheduled Tribes and Hilly area beneficiaries and to the others the extent of subsidy is 50 per cent.

Solar Cookers

The Department is subsidising the cost of solar cookers to the extent of 31-1|3 per cent subject to a maximum of Rs. 150|- per cooker. In addition to this some State Governments also provide subsidy on solar cookers.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अमरीका में एक नई परियोजना का स्थापित किया जाना

1432. **श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :**
श्री रशीद मसूद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1988 के इकोनोमिक टाइम्स में "भेल मस्ट थिंक अगेन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई परियोजना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और क्या यह सच है कि आर्थिक संकट के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड कम्पनी देश में विद्युत् उत्पादन संबंधी उपकरणों के लिए दिए गए स्वयं अपने देय आर्डरों को ही पूरा नहीं कर पा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में जबकि यह कम्पनी यहां के आदेशों को ही पूरा नहीं कर पा रही है तो इसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में विदेश में एक नयी परियोजना हाथ में लिए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकार का ध्यान 13-4-88 के इकोनोमिक टाइम्स में भेल यमस्ट थिंक अगेन" शीषक के अन्तर्गत प्रकाशित सपादकीय की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) से (घ) आने वाले वर्षों में लगातार उत्पादन बनाए रखने के लिए बी०एच ई०एल० नए क्षेत्रों में विविधीकरण की योजना बना रही है । इस संदर्भ में, बी०एच०ई०एल० सिलिकान बेली यू० एस० ए० में एप्लिकेशन स्पेसिफिल इंटिग्रेटिड सर्किटों के क्षेत्र में प्रवेश करने की संभाव्यता का पता लगा रहा है ।

बी०एच०ई०एल० बिजली उत्पादन उपकरणों के संभरण के लिए डिलीवरी अनुसूचियों को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर सक्षम है ।

बी०एच०ई०एल० में कोई आर्थिक संकट नहीं है क्योंकि कम्पनी पिछले कई वर्षों से निजी संसाधान बढ़ा रही है और लाभ कमा रही है । विदेश से परियोजना लगाने से कम्पनी के देश में लगे हुये कार्य संचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टायरों के मूल्यों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा मूल्यांकन

1433. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने गत वर्ष टायरों के मूल्यों का मूल्यांकन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मूल्यांकन करते समय ब्यूरो ने टायरों की कीमतों को उनकी न्यायोचित कीमतों से अधिक पाया ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाये है , और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध मे उठाय गये कदमों के क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ). औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने मई, 1986 में निर्विष्टियों को विद्यमान लागत के आधार पर टायरों का उचित प्रमाणिक मूल्य सुझाया था किन्तु चूंकि रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद में, टायर बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कई विनिष्टियों की लागत काफी बढ़ गई थी, इसलिए सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से अपनी सिफारिश अद्यतन बनाने का अनुरोध किया है ।

Criteria for foreign collaborations in essential and non-essential items

1434. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the criteria for allowing foreign collaborations in both essential and non-essential items; and

(b) whether in all such collaborations provisions to extend know how for establishing suitable auxiliary industries are included?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Import of technology is governed by the Technology Policy statement of the Government. The basic principles/governing the import are that it is permitted only on selected basis where the need has been established, technology does not exist within the country, the time taken to generate the technology indigenously would delay the achievement of development targets etc. Requests for technology import are, therefore, considered based on the above governing principles after due evaluation.

(b) Normally requests for import of knowhow for establishing auxiliary industry are not made in the collaboration proposals. However, where such requests are made, these are considered on merits by the Government.

चन्द्रसिंह गढ़वाली के सम्मान में स्मारक डाक टिकट का जारी किया जाना

1435. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा काला पानी की सजा पाने वाले श्री चन्द्र सिंह गढ़वाली, जिनकी 1 अक्तूबर, 1979 को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल;